>

Title: Need to set up the headquarters of all the Central Establishments in Jharkhand.

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): उपाध्यक्ष महोदय, यह संयोग की बात है कि आप चेयर पर है और आप जिस राज्य से आते हैं, मैं उसी के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। यदि किसी ने गरीबी, पिछड़ापन देखना हो तो उसे झारखंड आना चाहिए। झारखंड में 70 परसेंट से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। हम कोयला उत्पादन करते हैं लेकिन कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। हमारे यहां बीसीसीएल, सीसीएल है। ईसीएल के लाभ का भाग भी हमारे यहां है लेकिन इसके बावजूद कोल इंडिया का हेडक्वार्टर वहां है। हम कॉपर उत्पादन करते हैं लेकिन उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। हम यूरेनियम उत्पादन करते हैं लेकिन उसका हेडक्वार्टर मुम्बई में है। यहां के पानी से दामोदर वैली कॉरपोरेशन बनता है लेकिन इसका भी हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। मैसांजोर डैम दुमका में है, मैथन डैम धनबाद में है, पंचायत डैम है, हमारी जमीन है, हमारा पानी है लेकिन हमारे किसान इससे सिंचाई नहीं कर पाते हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि कोल इंडिया, ईसीएल, हिन्दुस्तान कापर, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटिड, दामोदर वैली कॉरपोरेशन का हैडक्वार्टर हमारे यहां होना चाहिए। हमारे लोग पैसे के अभाव में मरते हैं, लोग गरीब माने जाते हैं, हमें रायल्टी नहीं मिल रही है, टैक्स का भाग नहीं मिल रहा है, हम झारखंड में उत्पादन कर रहे हैं, वे हमारे पैसों से पल रहे हैं। इसलिए टाटा जैसी प्राइवेट कंपनी का हैडक्वार्टर हमारे यहां होना चाहिए। मेरा केंद्र सरकार से मेरा आग्रह है कि केंद्र सरकार मैसांजोर, मैथन और पंचायत के पानी का बंटवारा ठीक तरह से करे ताकि झारखंड के किसानों को इसका फायदा मिले।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): महोदय, मैं अपने आपको इस मामले के साथ संबद्ध करता हूं।